

प्रेषक

एन0एस0नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव,  
गृह विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2008

विषय:-तहसील टनकपुर के ग्राम टनकपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का आवागमन शिविर की स्थापना हेतु कुल 0.401 है0 (1 एकड़) भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी धम्पादत के पत्र संख्या-371/सात-01/2004-05 (भू0आव0) दिनांक 25 दिसम्बर, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का आवागमन शिविर की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या- 258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों अनुसार भारत सरकार के सेवारत विभागों को नियमानुसार निर्धारित दरों पर राज्य सरकार की भूमि तहसील टनकपुर के ग्राम टनकपुर के खाता खतौनी नं0 201 के खसरा नं0- 479/2 मध्ये 0.401 है0 (01 एकड़) भूमि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण

...(2)

कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सर नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2% से कम नहीं होगा।

- (4) प्ररनगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
  - (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा निगम आवटी संस्था का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
  - (6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं० 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्ररनगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन०एस० नपलच्याल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4- सेनानी, 14वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जाजरदेवल, पिथौरागढ़।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)  
अनुसचिव।